

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1873
जिसका उत्तर गुरुवार, 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

1873 श्री महेश पोद्दार:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों में नियुक्त किये गए न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तथा तत्संबंधी राज्य और जाति-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या सहित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार / सर्वोच्च न्यायालय के पास वर्तमान में कोई नियुक्ति लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कब तक इस पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरन रीजीजू)

(क) से (ग) : विगत चार वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के ब्यौरो को दर्शाने वाला एक विवरण **उपाबंध-क** के रूप में उपबद्ध हैं ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविदान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है जो व्यक्ति की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं अतः कोई जाति/प्रवर्ग-वार डाटा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है ।

उच्च न्यायालयों में 1104 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के विरुद्ध, 404 रिक्तियों को छोड़कर उच्च न्यायालय में 700 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की वर्तमान पद संख्या और रिक्त पदों के ब्यौरे **उपाबंध-ख** पर संलग्न है । वर्तमान में, 171 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के

बीच विभिन्न स्तरों पर है । उच्च न्यायालयों में 233 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय कॉलेजियम से और सिफारिशें अभी प्राप्त होनी है ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है, इसके लिए राज्य और केन्द्रीय स्तर दोनों पर विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है, यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रतापूर्वक भरे जाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र या उन्नयन के कारण और न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि के कारण भी उद्भूत होती रहती है ।

उपाबंध-क

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	विगत चार वर्षों के दौरान नियुक्तियों की संख्या				कुल
		2018	2019	2020	2021	
1	इलाहाबाद	28	10	04	17	59
2	आंध्र प्रदेश	-	02	07	02	11
3	बॉम्बे	04	11	04	06	25
4	कलकत्ता	11	06	01	08	26
5	छत्तीसगढ़	04	-	-	03	07
6	दिल्ली	05	04	-	02	11
7	गुवाहाटी	02	04	-	06	12
8	गुजरात	04	03	07	07	21
9	हिमाचल प्रदेश	-	02	-	01	03
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	02	-	05	02	09
11	झारखंड	03	02	-	04	09
12	कर्नाटक	12	10	10	06	38
13	केरल	04	01	06	12	23
14	मध्य प्रदेश	08	02	-	08	18
15	मद्रास	08	01	10	05	24
16	मणिपुर	-	-	01	-	01
17	मेघालय	01	01	-	-	02
18	उड़ीसा	01	01	02	04	08
19	पटना	-	04	-	06	10
20	पंजाब और हरियाणा	07	10	01	06	24
21	राजस्थान	-	03	06	08	17
22	सिक्किम	-	-	-	-	-
23	तेलंगाना	-	03	01	07	11
24	त्रिपुरा	01	-	01	-	02
25	उत्तराखंड	03	01	-	-	04
	कुल	108	81	66	120	375

विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्वीकृत, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियों का ब्यौरा

क.सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्तियां		
		स्थाई	अति.	कुल	स्थाई	अति.	कुल	स्थाई	अति.	कुल
1	इलाहाबाद	120	40	160	74	19	93	46	21	67
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	26	0	26	2	9	11
3	बॉम्बे	71	23	94	51	7	58	20	16	36
4	कलकत्ता	54	18	72	31	8	39	23	10	33
5	छत्तीसगढ़	17	5	22	10	3	13	7	2	9
6	दिल्ली	45	15	60	34	0	34	11	15	26
7	गुवाहाटी	18	6	24	17	6	23	1	0	1
8	गुजरात	39	13	52	32	0	32	7	13	20
9	हिमाचल प्रदेश	10	3	13	8	1	9	2	2	4
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	13	0	13	0	4	4
11	झारखंड	19	6	25	19	1	20	0	5	5
12	कर्नाटक	47	15	62	39	6	45	8	9	17
13	केरल	35	12	47	27	12	39	8	0	8
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	35	0	35	5	13	18
15	मद्रास	56	19	75	44	15	59	12	4	16
16	मणिपुर	4	1	5	3	1	4	1	0	1
17	मेघालय	3	1	4	3	0	3	0	1	1
18	उड़ीसा	24	9	33	21	0	21	3	9	12
19	पटना	40	13	53	25	0	25	15	13	28
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	43	6	49	21	15	36
21	राजस्थान	38	12	50	26	0	26	12	12	24
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	19	0	19	13	10	23
24	त्रिपुरा	4	1	5	5	0	5	-1	1	0
25	उत्तराखंड	9	2	11	7	0	7	2	2	4
	कुल	833	271	1104	615	85	700	218	186	404
